बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा चलाई जा रही कम्पनियों के बारे में शिकायतें

+

227. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री सुभाष आहूजा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृह देश में कुल कितनी कम्पनियां चला रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को हाल में इन कम्पनियों के विरुद्ध भ्रष्ट तरीकों को अपनाने और कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है , और

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ). एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

"बड़ा औद्योगिक घराना" कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित नहीं है । तथापि 1031 कम्पनियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 20 (क) के साथ पठित धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई हैं । इनमें से बहुत सारी कम्पनियां बड़े औद्योगिक घरानों की हैं ।

कम्पनी कार्य विभाग अनेक स्रोतों से अनेक प्रकार की शिकायतें बड़े औद्योगिक घरानों से ताल्लुक रखने वाली कम्पनियों समेत कम्पनियों के खिलाफ करता रहा है । 1976-77 के वर्ष में जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, 5071 शिकायतें मिली थीं, जिनमें धोखाधड़ी, कुप्रबन्ध, धन के गबन, अधीन आदि आदि की शिकायतें शामिल थीं । प्रत्येक शिकायत की जांच पड़ताल होती है और उचित कार्यवाही की जाती है । और बहुत बड़ी संख्या होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि शिकायत का विवरण दिया जाय और उन पर की गई कार्यवाही बताई जाये । तथापि, यदि माननीय सदस्य अब बड़े घराने द्वारा चलाई जा रही किसी विशेष कम्पनी के बारे में सूचना चाहते हैं तो उसे दिया जा सकता है ।

श्री भारत सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत व्यापक था, लेकिन जो उत्तर दिया गया है, वह इतने संक्षेप में दिया गया है कि उस का कोई अर्थ नहीं निकलता है । इन बड़े घरानों के सम्बन्ध में देश को वर्षों से चिन्ता थी, ये लोग मास-प्रेक्टिसिज करते थे, इकानामिक पावर्स का कन्सेंट्रेशन इन के पास था, इसी कारण से मोनापोलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसिज बिल लाया गया और यहां पास हुआ । जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उस में यह बताया गया है कि "बड़े औद्योगिक घरानों" की परिभाषा कम्पनी कानून में नहीं है । यह बड़े अफसोस की बात है—जब बड़े औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में इतने दिनों से मामला चल रहा है, तो यह त्रुटि कम्पनी कानून में क्यों रह गई, अभी तक इस को दूर क्यों नहीं किया गया ? इस तरह के घराने जो देश में एक दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं, शासन को कानून की इस त्रुटि को अब तक दूर कर देना चाहिये था ।

मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि मुख्य रूप से उन कम्पनियों के नाम बतलाइये, लेकिन कोई नाम नहीं दिये गये । मैं आप को बतलाना चाहता हूं—बिड़ला, जे0 के0, डालमिया, साहू जैन, बाजोरिया, थापर, जयपुरिया, मोदी, इन सब पर इन्कम टैक्स चुकाने के बारे में पैनल्टी की कार्यवाही चल

रही है । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक शासन ने इन के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

कुछ ऐसी भी फर्में हैं जिन के खिलाफ एम० आर० टी० पी० एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है । जैसे कलकत्ता कैमिकल्ज कम्पनी लि०, आदि अनेक कम्पनियां हैं । आपने जो जवाब दिया है, वह बहुत ही संक्षिप्त है, मैं ऐसी अनेकों कम्पनियों के नाम बतला सकता हूं, जिन के खिलाफ अरबों-करोड़ों रुपये का मामला इन्वाल्व्ड है—आप को कम से कम ऐसी कम्पनियों के नाम बतलाने चाहिये थे ।

श्री शान्ति भूषण : मान्यवर, लार्ज इण्डस्ट्रीयल हाउसेज का जो विवरण दिया गया है, इस में यह कहा गया है कि कम्पनीज एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एम० आर०टी०पी० एक्ट में डिफाइन किया गया है तथा इस एक्ट के हिसाब से जो कम्पनियां लार्ज-इण्डस्ट्रीयल हाउसेज की डेफिनीशन में आती है—उन की संख्या 1031 है । अब इन 1031 कम्पनियों के खिलाफ क्या क्या शिकायतें आई हैं, यह बतलाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन जैसा कि इस विवरण पत्र में कहा गया है— यदि किसी स्पेसिफिक कम्पनी के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते तो आप प्रश्न पूछिये, उस के बारे में जरूर उन को पूरी जानकारी दी जायगी ।

लार्ज और जो लार्ज नहीं है, उन सब के बारे में 5071 शिकायत हमारे पास आई हैं । हमारे यहां इन दोनों के लिये अलग-अलग स्टेटिस्टिक्स नहीं रखी जाती है । लेकिन 5071 कम्पलेंटस इन सब आई हैं और उन को डील किया गया है और एप्रोप्रियेट एक्शन लिया गया है । अगर माननीय सदस्य किसी खास कम्पनी के बारे में जानना चाहेंगे, तो जानकारी जरूर दी जायगी ।

श्री भारत सिंह चौहान : यह सर्वविदित है कि इन जो बड़े घराने हैं, उन में डेढ़ करोड़ के करीब कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं और उन की सेक्यूरिटी जो है, उन की जीविका और उनका भविष्य इन बड़े घरानों पर ही निर्भर होता है और उन को कोई सुरक्षा नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इन डेढ़ करोड़ कर्मचारियों के सम्बन्ध में उन की सुरक्षा के बारे में कोई विचार सरकार कर रही है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के जो कानून हैं, जो नियम हैं, उन के अन्तर्गत उन की सेफ्टी और उन की जीविका की सुरक्षा हो, ऐसा कोई प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

श्री शान्ति भूषण : जो प्रश्न किया है, उस का आशय मैं समझ नहीं पाया हूं । बड़े घरानों के उद्योगों में जो डेढ़ करोड़ कर्मचारी लगे हुए हैं, उन की सुरक्षा का जो प्रश्न किया है, वह किस प्रकार की सुरक्षा से सम्बन्ध रखता है, मैं ठीक से उस को समझ नहीं पाया हूं ।

श्री भारत सिंह चौहान : उन से ज्यादा काम लिया जाता है, समय से ज्यादा काम लेते हैं । . . . (व्यवधान) . . .

MR. SPEAKER: It does not arise from the question.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री जी ने प्रश्न का आशय नहीं समझा है, यह मैं कह रहा हूं ।

श्री भारत सिंह चौहान : उन से ज्यादा काम लिया जाता है, मेरे प्रश्न का यह आशय है ।

MR. SPEAKER: That question does not arise really.

श्री शान्ति भूषण : यह विभाग कम्पनी ऐफेयर्स डिपार्टमेंट का जो है, यह कम्पनीज एक्ट में जो प्रावधान हैं या मोनोपलीज एक्ट

में जो प्रावधान हैं, उन के लिए है । और दूसरे विभाग हैं जिन में और दूसरी तरह की शिकायतें आती हैं और उन में उन की जांच की जाती है । जो भी शिकायत किसी भी कम्पनी के विरुद्ध कम्पनीज एक्ट से सम्बन्ध रखते हुए, या मोनोपोलीज एक्ट से सम्बन्ध रखते हुए, आती है, उस पर पूरा विचार किया जाता है और उस की जांच कराई जाती है और जो भी उस के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही होनी है, वह जरूर की जाती है ।

SHRI BIJOY SINGH NAHAR Will the Minister let us know whether these companies are not paying provident fund dues for a long time?

SHRI SHANTI BHUSHAN The hon Member has put the question as to whether these companies have not been paying provident fund. There are thousands of large companies. So far as large industrial houses are concerned, as defined in the Monopolies Act, even there the number of undertakings is as large as 1031 So, unless the question is specific, it is very difficult to answer

Apart from this, so far as provident fund is concerned, provident fund is the concern of the Labour Ministry. It is not related to the Company Affairs Department. Perhaps, the question could most appropriately be put to the Labour Ministry.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the hon. Minister kindly tell us, he has given a figure, horrifying figure of 5071 in one financial year i.e. 1976-77 for such malpractices and crimes, out of 5071 in how many cases the complaints or charges of allegations have been established and which are the broad categories in which they are involved?

SHRI SHANTI BHUSHAN: I can indicate the broad categories to which these 5071 complaints relate to. They are: non-payment of Public Deposits, mis-management, non-payment of dividends, non-receipt of balance sheets, non-receipt of notices, non-registration of transfer of shares, non-issue of share certificates, improper holding of meetings, non-holding of annual meetings, non-receipt of dividend warrants, mis-appropriation, fraud, mis-application of funds, improper election of directors, failure to allow inspection of minute books and other complaints which are mategorised as miscellaneous (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU Sir, he will answer now part (2) of my question.

SHRI SHANTI BHUSHAN While 5071 complaints under different heads were received during the year 1976-77, as many as 5060 were disposed of during this period of 1976 77. Obviously, what action was taken on what companies

MR SPEAKER: You are not in a position to say.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I wanted to know, out of these 5071, in how many cases the allegations or the charges have been established and what action has been taken. I asked a specific question. He has given in his reply that there are figures available. 5071 were received in the year 1976-77. Out of 5071....

MR. SPEAKER: He said, 5000 and odd were disposed of. He is not in a position to say which company...

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Why are you replying for the Minister?

MR. SPEAKER: No, he has answered it. Please see the record. Obviously he has answered it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You cannot run the House like this.

MR. SPEAKER: He has answered it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let him repeat it.

MR. SPEAKER He is not required to repeat it. Please look into the record

SHRI JYOTIRMOY BOSU. You can't say like that Let him say in how many cases the complaints have been established He has not answered that

MR SPEAKER Mr Bosu, he has answered that 5000 and odd complaints were received He is not in position to say

SHRI JYOTIRMOY BOSU He has not said that Let him answer

MR SPEAKER Mr Bosu, you are not to dictate anything Now, Mr Venkatasubbaiah

SHRI JYOTIRMOY BOSU I am on my legs

MR SPEAKER No nothing Mr Venkatasubbaiah

(Interruptions)

SHRI P VENKATASUBBAIAH The hon Minister said that these complaints include allegations including misapplication of funds also That is what he has said And there are 5071 complaints in one year and action on many of them has been taken May I know in this connection whether any complaint or complaints have been made to the Minister that taking advantage of the scarcity conditions prevailing in this country with regard to cement, certain big industrial houses through fradulent means and misapplication of funds are trying to establish certain factories particularly in Andhra Pradesh, and also they are buying up certain companies. In that case, I want to know whether any allegations have been made that these big business people are trying to take full advantage of it and depriving the local people of having an industry either in the private sector of that area or in the State sector.

SHRI SHANTI BHUSHAN In regard to complaints relating to misapplication of funds, all that I am in a position to say at the moment is .

MR. SPEAKER You say you require notice

SHRI SHANTI BHUSHAN . that six complaints of this kind were received during the year 1976 There was one outstanding complaint from before, and out of the seven, three were disposed of and four were remaining to be disposed of About the specific nature of complaint which has been referred to, I would require notice for it

MR SPEAKER Mr Saugata Roy

SHRI SAMAR GUHA For the last three days I have been trying to catch your eye

SHRI SAUGATA ROY I would like to know from the hon Minister whether the Sarkar Commission of Inquiry set up to probe into the allegations of issue of duplicate shares and income-tax fraud against Birlas have submitted their report and if so, what are the contents of the report, and if not, why the report has not been submitted and when it will be submitted

SHRI SHANTI BHUSHAN I would require specific notice for it

MR SPEAKER He requires a specific notice Now Mr Samar Guha

PROF DILIP CHAKRAVARTY. Sir I want to ask

MR SPEAKER You have already put the question You cannot put on every question

PROF DILIP CHAKRAVARTY My difficulty is, I am not getting an opportunity . .

(Interruptions)

SHRI SAMAR GUHA: I want to know from the hon. Minister, about the complaints that he received or the steps taken against those companies, and how many of these companies belong to the first 25 of the big industrial houses

SHRI SHANTI BHUSHAN As I said earlier, no separate statistics are kept in regard to these complaints as to whether they relate to large industrial houses or whether they belong to other companies. But if the hon Member has any specific companies in mmd, then if he gives any notice I shall supply him the necessary details.

SHRI SAMAR GUHA At least give us a few names out of the first 25, say, 5, 10, 15 or 20 like Birlas Bajorias, Tatas etc At least give us a few names

MR SPEAKER Are you in a position to give it?

SHRI SHANTI BHUSHAN If the hon Member wants to know how many complaints were received against Tatas or Birlas, or any other large industrial house, unless I get the figures worked out on that basis, I cannot supply those figures, because the question was of a very general nature It related to large industrial houses, which included 1,031 undertakings It is not possible to supply the information without notice

SHRI SAMAR GUHA Would you kindly agree to supply the details?

SHRI SHANTI BHUSHAN Whichever information he wants can be supplied.

SHRI SAMAR GUHA: My question was about the first 25 houses.

SHRI SHANTI BHUSHAN It would be a very large number If you restrict it to a few numbers, it would be possible

SHRI SAMAR GUHA: I was enquiring about the first 25 houses

SHRI SHANTI BHUSHAN: Even for the first 25 houses, the number of undertakings would be very large.

PROF DILIP CHAKRAVARTY: Sir, it is an important question I want to ask a supplementary

MR SPEAKER Next question. Shri C N. Visvanathan

PROF DILIP CHAKRAVARTY: Sir, you must be permitting questions on this Tatas and Birlas are creating artificial scarcity in soda ash It is very unfortunate that you are acting as a baffled wall of this House, of this Lok Sabha

Amendment to the Representation of People Act

*231 SHRI SAMAR GUHA Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state

(a) whether Government are considering amendment of present Representation of People Act;

(b) whether misuse of political power and abuse of administrative authority will be considered as an offence for debarring a person from contesting any election according to constitutional provisions, and

(c) if so facts thereabout?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) (a) Yes, Sir.

(b) This matter is also under examination

(c) Does not arise

SHRI SAMAR GUHA: According to our constitutional provisions and also according to the Representation of the People Act, there is no provision to catch political criminals who create a lot of misery for our people.